



# अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.  
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : [abvpkendra@gmail.com](mailto:abvpkendra@gmail.com)

दिनांक: 16 अप्रैल 2023

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

अभाविप की केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक देहरादून में सम्पन्न।

**'शिक्षा के अवसर सभी के लिए हों उपलब्ध, बाधाएं दूर करने की दिशा में शीघ्र प्रयास हों: अभाविप।'**

आज रविवार शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दून विश्वविद्यालय, देहरादून में चल रही केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न हुई। 15-16 अप्रैल, 2023 के मध्य अभाविप की इस बैठक में देशभर के सभी राज्यों से उपस्थित अभाविप कार्यकर्ताओं, प्राध्यापकों ने शिक्षा, समाज से जुड़े विषयों पर मंथन किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देशभर में 45,59,410 सदस्यों और 3963 नगर इकाईयों व 8658 महाविद्यालय इकाईयों के विस्तार के साथ विश्व का सबसे बृहत् छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में पूरे देश से उपस्थित प्रतिनिधियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार सुधार, युवाओं को नवाचारों से जोड़ने, सभी के लिए शिक्षा की सुलभता तथा पर्यावरणीय विषयों के प्रति जागरूकता आदि विषयों पर अपने मत रखे।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजशरण शाही ने कहा कि, "आज शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय युवा संभावनाओं को यथार्थ धरातल पर उतारने में सामर्थ्यवान है। आज की युवा शक्ति को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने में समाज व सरकार सहित देश के जिम्मेदार नागरिकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अभाविप की केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक में युवाओं के नेतृत्व में विभिन्न सकारात्मक गतिविधियां संचालित करने की योजना पर विचार हुआ है, जिसको मूर्त रूप देने के लिए अभाविप की सभी इकाइयां तथा कार्यकर्ता प्रयास करेंगे।"

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, "अभाविप की मांग है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन के लिए शीघ्रता से प्रयास किए जाएं। आज देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के निर्धारित पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही, इन रिक्तियों को मिशन मोड पर भरना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण न हो, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो व शिक्षा शुल्क सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक पहुंच के भीतर हो। वर्तमान में बहुविषयक शिक्षा मॉडल की दिशा में कार्य हो रहा है, यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक छात्र को उसकी रुचि के अनुसार विषयों के व्यापक चयन के अवसर मिलें। वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न रूपों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके समूल निर्मूलन की आवश्यकता है, इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगंबर पवार द्वारा जारी की गयी है।)